शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया। देश की 10 विधानसभा समेत देशभर में खाली 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:29 अंक:246 दिनांक:17-08-2024 शनिवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के छात्र ने दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उदयपुर में तनाव फैल गया। हिन्दू संगठनों ने शहर के शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की।

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान...

जम्मू-कश्मीर में 18,25सितंबर और1अक्टूबर को वोटिंग :हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग; नतीजे 4 अक्टूबर को

जम्मू में 3 और हरियाणा में 1 चरण में मतदान

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव का ऐलान किया है। वहीं, हरियाणा में एक चरण में मतदान का ऐलान किया है। दोनों राज्यों में 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू-कश्मीर में 3 फेज,18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। यहां 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। उधर, हरियाणा में एक फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार ने बताया कि सिक्युरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा-महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे।

जम्मू कश्मीर में चुनाव का शेडयूल

जम्मू कश्मीर में पहले फेज के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी होगा, वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त होगी। 18 सितंबर को चुनाव होंगे। वहीं, दूसरे फेज के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 29 अगस्त को जारी होगा, वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 5 सितंबर होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 सितंबर होगी। 25 सितंबर को चुनाव होंगे। तीसरे चरण के लिए गैजेट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगा, वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर होगी। एक अक्तूबर को चुनाव होंगे। इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं किसी चुनाव में हुआ तो वह लोकसभा चुनाव 2024 था। ये चुनाव उत्सवी माहौल में हुए। युवाओं-महिलाओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिला। जब-जब विश्व में चुनाव होंगे, आपको निश्चित रूप से हमारे देश में हुए चुनाव की याद आती रहेगी। ये चुनाव हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाते रहेंगे।

हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक अक्तूबर को मतदान होगा। चार अक्तूबर को रिजल्ट आएगा। वोटर सूची 27 अगस्त को जारी होगी। इस बार हरियाणा में स्लम और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अलग से पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। सभी पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और वोटर हेल्पलाइन की वेबसाइट जारी रहेगी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। पिछली बार भाजपा 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद भाजपा ने दस सीटें जीतने वाली जजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं। एक-एक सीट इनेलो और हलोपा के खाते में आई थी। सात सीटें निर्दलीयों ने जीती थी।

कोरोना के बाद अब मंकीपॉक्स का खतरा, डब्लू एचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की

नई दिल्ली (ईएमएस)। दुनिया में कोरोना के बाद अब मंकीपॉक्स का खतरा आ गया है। मंकीपॉक्स कोरोना की तरह महामारी बनता जा रहा है। डब्लूएचओ ने भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर कर दी है। मंकीपॉक्स अफ्रीका से बाहर भी फैल गया है।अफ्रीका से बाहर स्वीडन में भी इसका मरीज मिला है। अफ्रीकी देशों में मंकीपॉक्स के कारण अब तक 100 लोगों की जानें जा चुकी है। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारियों का कहना है कि जिस शख्स को मंकीपॉक्स हुआ है, वह कुछ दिनों पहले अफ्रीका से होकर आया था। जिसका इलाज स्टॉकहोम में हो रहा है।

मंकीपॉक्स के विशेषज्ञ ने कहा है कि जहां पर मंकीपॉक्स क्लैड 1 फैला हुआ है, वहां पर पहले भी पीड़ितों के इलाज किया जा चुके हैं, लेकिन इस बार एजेंसी खास एतिहात बरत रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि साल में यह दूसरी बार हो रहा है जब डब्लूएचओ ने मंकीपॉक्स की वजह से इमरजेंसी घोषित की है। इसके पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इस वेरिएंट के मरीज देखने मिले थे।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मंकीपॉक्स की वजह से 450 लोगों की मौत हो गई थी। अफ्रीकी देशों के मध्य और पूर्वी इलाकों में यह वेरिएंट ज्यादा फैला था। इस बार जो वेरिएंट फैल रहा है उसकी चपेट में 15 से ज्यादा देश आ गए हैं। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन ने बीते सप्ताह बताया था कि मंकीपॉक्स की वजह से अब तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया भर को अलर्ट पर हो जाना चाहिए। मंकीपॉक्स क्लैड 1 की बात करें तो वह ज्यादा तेजी से फैल रहा है और शारीरिक तौर पर यह चिंता की बात है, क्योंकि इसमें शरीर पर गांठदार दाने बनते जाते हैं और तेज बुखार होता है। मंकीपॉक्स के होने से शरीर में और असहनीय या दर्द होने लगता है, जिसके इलाज के बारे में अब तक विशेषज्ञों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है।

राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी.....डिप्टी सीएम दीया ने की 5 अपील

जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान में पिछले 15 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, करौली, झुंझुनूं और पाली सहित कई जिलों में तेज बारिश के चलते हादसे हुए। वर्षाजनित हादसों पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जलभराव वाले इलाकों पर सघन रूप से निगरानी रखें और प्रभावित लोगों को तत्काल रूप से मदद पहुंचाए। सीएम के निर्देश के बाद अमूमन सभी जिला कलेक्टर लगातार फील्ड का दौरा कर जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। राजधानी जयपुर में हो रही भारी बारिश के चलते कुछ ब्लॉक में जिला कलेक्टर ने कक्षा एक से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।

राजस्थान के अलग अलग जिलों में पिछले एक सप्ताह में कई हादसे हुए। इन हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 11 अगस्त को भरतपुर के श्रीनगर गांव में एक साथ 6 युवक पानी में बह गए थे। 11 को ही जयपुर के कानोता बांध में डूबने से 5 दोस्तों की मौत हो गई थी। जयपुर के गलता कुंड में डूबने से दो युवकों और हथनी कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो चुकी है। झुंझुनूं के सिंघाना क्षेत्र में स्थित मेहराणा गांव के पास तालाब में डूबने से 3 युवकों की जान चली गई थी। करौली में एक जर्जर मकान ढहने से पिता पुत्र और तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई थी। बांसवाड़ा, जोधपुर और पाली में हुए अलग अलग हादसों में भी कुछ युवाओं की अकाल मृत्यु हुई है। टोंक जिले में भी एक रोडवेज चालक पानी के बहाव में बह गया था जिसकी लाश सात दिन बाद मिली। अजमेर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई।

डिप्टी सीएम कुमारी ने मौसम विभाग की ओर से जारी की गई बारिश की चेतावनी को अपने अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से 5 अपील की है। लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है ताकि बारिश के दौरान होने वाले हादसों के शिकार होने से बचा जा सके। बरसात के मौसम में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे की मदद करें। जलाशयों और जलभराव के क्षेत्रों से दूर रहें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें।अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। पेड़ों के नीचे शरण ना लें और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें।

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले-2047 तक पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प

नई दिल्ली (ईएमएस)। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75 हजार मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। पीएम ने कहा कि 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में तीन गुना काम करूंगा। ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। अब दुनिया के लिए डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है, अब इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं।

वहीं कोलकाता रेप-मर्डर पर उन्होंने कहा- ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई-बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है।

हर चुनौती पार करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वज सिर्फ 40 करोड़ थे, उन्होंने गुलामी जंजीरों को तोड़ दिया था। हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, तो 140 करोड़ नागरिक अगर संकल्प लेकर चल पड़ें, तो चुनौतियां कितनी बड़ी क्यों न हो, हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि देशवासियों ने अपने अनुभव से हमें विकसित भारत बनाने के सुझाव दिए हैं।

खुलासा....हसीना के लिए भारत ने की थी बाइडेन प्रशासन से लॉबिंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना को हाल ही में पद से हटने के बाद पड़ोसी देश में उठापटक को दौर जारी है। इस बीच पिछले एक साल में भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच जटिल कूटनीतिक लेन-देन के बारे में रिपोर्टें सामने आई हैं। रिपोर्ट में दोनों देशों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि उन्हें पद से हटाने से एक साल पहले, भारतीय राजनयिकों ने बांग्लादेश की लंबे समय से सत्तावादी प्रधानमंत्री हसीना पर दबाव कम करने के लिए अपने अमेरिकी समकक्षों से सक्रिय रूप से पैरवी की थी।

बाइडेन प्रशासन जनवरी में विवादास्पद चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों और कथित मानवाधिकार हनन पर कठोर कार्रवाई के लिए हसीना की आलोचना करता रहा है। अमेरिका ने हसीना की कमान के तहत एक बांग्लादेशी पुलिस इकाई पर प्रतिबंध लगाया था, जिस पर न्यायेतर हत्याओं का आरोप था और लोकतंत्र को कमजोर करने में शामिल बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। जवाब में, विपक्ष के सत्ता में आने पर इस्लामी समूहों के संभावित उदय के बारे में चिंतित भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका से अपने लोकतंत्र समर्थक रुख को नरम करने का आग्रह किया।

रिपोर्ट में भारतीय सरकारी सलाहकार के हवाले से कहा गया है, आप इन्हें लोकतंत्र के स्तर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए, मुद्दे बहुत अधिक गंभीर हैं। भारतीय सरकारी सलाहकार ने कहा, अमेरिकियों के साथ बहुत सी बातचीत में कहा, यह हमारे लिए एक मुख्य चिंता का विषय है, और आप हमें रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं ले सकते, जब तक कि हमारे पास किसी तरह की रणनीतिक सहमति न हो। भारतीय अधिकारियों ने तर्क दिया था कि अगर विपक्ष को चुनाव में सत्ता हासिल करने की अनुमति मिलती हैं, तब बांग्लादेश इस्लामी गुटों के लिए पनाहगाह बन जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा।

इसके कारण बाइडेन प्रशासन ने अपनी आलोचना को नरम कर हसीना सरकार के खिलाफ आगे प्रतिबंधों की धमकियों को टाल दिया, जिससे कई बांग्लादेशी निराश हुए। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह एक सोचा-समझा कदम था जिसका संबंध भारतीय लॉबिंग से था।

बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने हसीना के आधिकारिक आवास पर मार्च किया, जिसके कारण उन्हें भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब नई दिल्ली और वाशिंगटन के नीति निर्माताओं को यह पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या उन्होंने बांग्लादेश में स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। बाइडेन प्रशासन जनवरी में विवादास्पद चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों और कथित मानवाधिकार हनन पर कठोर कार्रवाई के लिए हसीना की आलोचना करता रहा है।

अग्नि मिसाइल के जनक का निधन

हैदराबाद(ईएमएस)। देश के जाने-माने एयरोस्पेस साइंटिस्ट और अग्नि मिसाइल के जनक डॉ राम नारायण अग्रवाल का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में हैदराबाद स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। वे कुछ समय से बीमार थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। आरएन अग्रवाल ने भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। वे अग्नि मिसाइलों के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्हें अग्नि मैन के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1990 में पद्म श्री और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

मन नहीं लगता, दूसरी जेल में शिफ्ट करे.....कैदी 6दिन से भूख हड़ताल पर

जयपुर (ईएमएस)। जयपुर में बीते दोनों बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के शूटर रोहित राठौड़ के कारण भरतपुर का जेल प्रशासन परेशान है। शूटर राठौड़ पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है। कैदी राठौड़ का कहना है कि उसका मन नहीं लगता है, वह चाहता है कि दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। इसकारण शूटर राठौर को हॉस्पीटल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया है।

गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले को लेकर पुलिस ने शूटर रोहित राठौड़ को गिरफ्तार किया। रोहित अभी भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में बंद है। इस दौरान राठौड़ बीते 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है।

70वें नेशनल फिल्म अवाड्र्स का ऐलान, बेस्ट एक्टर चुने गए ऋषभ शेट्टी

नई दिल्ली,(ईएमएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को 70वें नेशनल फिल्म अवाड्र्स का ऐलान कर दिया हैं। नेशनल अवॉर्ड किसी भी फिल्ममेकर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होते हैं। इस बार ये अवॉर्ड उन फिल्मों को दिए गए हैं जिन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड ने एक जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया है।

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से आई, डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने 2022 में माइथोलॉजी बेस्ड कहानी से सिनेमा फैन्स का दिल जीता था। फिल्म देखने के बाद से ही लोग इसे नेशनल अवॉड्र्स के लिए जाने वाली फिल्म बता रहे थे। मलयालम सिनेमा के लेजेंड एक्टर मामूटी को भी उनकी दो बेहतरीन फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मजबूत दावेदार माना जा रहा था। पेश है इस बार फीचर बेस्ट फीचर फिल्म: आट्टम (मलयालम)

बेस्ट डेब्यू फिल्म बाय डायरेक्टर: प्रमोद कुमार (फौजा, हरियाणवी फिल्म) बेस्ट पॉपुलर फिल्म- कांतारा, बेस्ट फीचर फिल्म (राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को प्रमोट करने वाली): कच्छ एक्सप्रेस, बेस्ट एनिमेशन फिल्म-विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक): ब्रह्मास्त्र, बेस्टडायरेक्शन:सूरजबड़जात्या (ऊंचा ई),बेस्टएक्टर (लीड रोल): ऋषभ शेट्टी (कांतारा),बेस्ट एक्ट्रेस (लीड रोल): नित्या मेनन (तिरुचित्रा म्बलम), बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर:पवन राज मल्होत्रा (फौजा, हरियाणवी फिल्म) बेस्ट एक्ट्रेस (सपोर्टिंग रोल): नीना गुप्ता (ऊंचाई), बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट: श्रीपत (मल्लिका पुरम,मलयालम फिल्म),बेस्ट सिंगर (मेल): अरिजीत सिंह (ब्रह्मास्त्र), बेस्ट सिंगर (फीमेल): बॉम्बे जयश्री, साउदी वेलक्का सीसी. 225/2009 (मलयालम फिल्म)।

भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि वह केंद्र सरकार को इस मामले में ऐक्शन लेने को कहे। इसके अलावा कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार से मेरी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। अगस्त 2019 में सुब्रमण्यन स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वे वहां का पासपोर्ट रखते हैं।

स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उद्धरण देते हुए कहा था कि वह किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटिजनशिप लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिता का त्याग करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल, 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था।

इस नोटिस का विषय था- नागरिकता के संबंध में शिकायत। स्वामी का कहना था कि ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के राहुल गांधी निदेशकों में से एक हैं। उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था।

उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। अब स्वामी ने अदालत में कहा है कि मैंने कई बार इस शिकायत पर स्टेटस अपडेट केंद्र सरकार से पूछा है, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अब अदालत से मांग की है कि वह सरकरा से इस मसले पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे।

महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया

मुंबई, (ईएमएस)। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इन दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों तथा चुनाव परिणाम की तारीख की घोषणा की है। इस बीच उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा. दरअसल पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे. बहरहाल महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ? ये सवाल चुनाव आयुक्त से पूछा गया. इस पर उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया. दरअसल चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त मॉनसून चल रहा है. फिर एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इसलिए आज महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मानसून सीजन की वजह से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने में देरी हुई है. इसके बाद गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाने वाले हैं. इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है.

- कब समाप्त हो रहा विधान सभा का कार्यकाल

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने बाद भी चुनाव हो सकते हैं. यह विशेषाधिकार आयोग के पास है।

कोलकाता रेप-मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई हिरासत में

केंद्र का सरकारी अस्पतालों को निर्देश- हेल्थवर्कर्स पर हमला हो तो 6 घंटे में एफआईआर कराएं

कोलकाता (ईएमएस)। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को राधागोविंद कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया। एजेंसी ने उन्हें समन भी जारी किया था। वहीं, देशभर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया। मंत्रालय ने कहा है कि मेडिकल संस्थानों को हेल्थकेयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही एफआईआर दर्ज करानी होगी। मंत्रालय ने ये फैसला मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले और 14 अगस्त को इसी कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर लिया।

शुक्रवार को ही सीबीआई टीम क्राइम सीन पर 3डी लेजर स्कैनर लेकर पहुंची। इससे डिजिटल ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा, जिससे पता चल सकता है कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे।

जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंससेपहले200अधिकारियों का तबादला

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 200 अधिकारियों का तबादला किया गया है। स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में 10 जिलों के एसएसपी, 5 जिलों के उपायुक्त भी शामिल हैं। खुफिया शाखा को भी नया प्रमुख मिल गया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीन अलग-अलग आदेशों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू-कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद ये फैसला लिया गया। 30 सितंबर को आर आर स्वैन के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभात बल के प्रमुख की भूमिका संभालेंगे। पुलिस बल में ये घटनाक्रम तथा अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्तियां केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यहां 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, प्रशासन के हित में यह आदेश दिया जाता है कि नीतीश कुमार, आईपीएस (एजीएमयूटी: 1999) एडीजीपी सीआईडी को सीआईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक अलग आदेश में सरकार ने पुलिस महानिरीक्षकों (आईजीपी) और उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) सहित 12 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया।

सरकार ने पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) के डीआईजी अजीत सिंह को भी स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें डीआईजी यातायात कश्मीर के पद पर तैनात किया गया है।

एक अन्य आदेश में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कई जिलों के पुलिस प्रमुखों को स्थानांतरित कर दिया, जिनमें जम्मू क्षेत्र के वे जिले भी शामिल हैं जहां हाल के महीनों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। जम्मू, रामबन, कठुआ, रियासी, उधमपुर, डोडा और पुंछ जिलों को नए पुलिस प्रमुख मिले हैं।

शैंपू की बोतल में मिली 20 करोड़ की कोकीन, विदेशी महिला गिरफ्तार

मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा की गई एक कार्रवाई में शैम्पू की बोतलों में 20 करोड़ रुपये की कोकीन मिली। इस मामले में नैरोबी से आई एक विदेशी महिला को डीआरआई ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. प्राप्त खबर के अनुसार डीआरआई को सूचना मिली थी कि एक विदेशी महिला कोकीन लेकर मुंबई आ रही है. जिसके बाद नैरोबी से आई लकी नाम की महिला को मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया. जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें शैंपू की दो बोतलें मिलीं। शैंपू की बोतलों में 1983 ग्राम चिपचिपा तरल पदार्थ पाया गया. इन बोतलों को जब्त कर लिया गया. जांच से पता चला कि उस चिपचिपे पदार्थ में कोकीन है. दरअसल महिला ने शैंपू की बोतलों में कोकीन छिपा रखी थी। जब्त की गई कोकीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है. इस मामले में मादक द्रव्य नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. डीआरआई ने बताया कि महिला फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई क्रिटि-कल मिनरल्स का एक्सपोर्ट बंद किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कई क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इसी कड़ी में चीन की सरकार ने अब एंटीमनी और उससे संबंधित एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। दुनिया में एंटीमनी के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी पिछले साल 48ज्ञ थी। यह एक स्ट्रैटजिक मेटल है जिसका इस्तेमाल कई तरह के सैन्य साजोसामान बनाने में होता है। इनमें गोला-बारूद, इन्फ्रारेट मिसाइल, परमाणु हथियार, नाइट विजन गोगल्स, बैटरी और फोटोवॉल्टिक इक्विपमेंट बनाने में होता है।

चीन की सरकार ने एक बयान में कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों तथा अग्रसार के अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए एंटीमनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चीन का कहना है कि यह पाबंदी किसी खास देश या रीजन के लिए नहीं है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह चीन की नई चाल है। एंटीमनी की सप्लाई बंद होने से अमेरिका और यूरोपीय देशों की सेनाओं पर सबसे ज्यादा असर होगा। चीन ने 15 सितंबर से छह तरह के एंटीमनी के प्रॉडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। इनमें एंटीमनी ओर, एंटीमनी मेटल्स और एंटीमनी ऑक्साइड शामिल है। साथ ही गोल्ड-एंटीमनी स्मेल्टिंग और सेपेरेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी। पिछले साल भी चीन कई क्रिटिकल मेटल्स की सप्लाई पर पाबंदी लगा चुका है। दिसंबर में चीन ने रेयर अर्थ मेग्नेट्स बनाने में काम आने वाली टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। उससे पहले ही वह क्रिटिकल मटीरियल्स को एक्ट्रैक्ट और सेपरेट करने में काम आने वाली टेक्लोलॉजी के निर्यात पर बैन लगा चुका था।

चीन ने कुछ ग्रेफाइट प्रॉडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। इसके अलावा गैलियम और जर्मेनियम का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है जिनका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में व्यापक इस्तेमाल होता है। बढ़ती डिमांड और टाइट सप्लाई के कारण इस साल एंटीमनी की कीमत रेकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। खासकर फोटोवॉल्टिक सेक्टर में इसकी मांग काफी बढ़ी है जहां इसका इस्तेमाल सोलर सेल की परफॉरमेंस सुधारने में होता है। चीन दुनिया में रिफाइंड एंटीमनी का सबसे बड़ा सप्लायर है लेकिन वह थाईलैंड, म्यांमार और रूस जैसे देशों से इसके अयस्क का आयात करता है।

ममता बनर्जी ने कोलकाता की महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध रैली का नेतृत्व किया

नई दिल्ली (ईएमएस)।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक विरोध रैली का नेतृत्व किया, जिसमें कोलकाता की महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की गई, जिसकी पिछले सप्ताह एक सरकारी कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आए हजारों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सांसदों ने आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए नारे लगाए। इस रैली से पहले भी ममता सीबीआई को जल्द जां

जन हितैषी

राजनीति की गैंगवार चरम अवस्था में

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में प्रशिक्षक महिला चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मृतक महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया है। उसके शरीर पर चोटों के निशान है। इस अपराध में एक से अधिक लोग शामिल होने की संभवना जताई गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सीमन पाया गया है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक से अधिक लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। कोलकाता पुलिस जब निर्धारित समय पर जांच पूरी नहीं कर पाई। तब पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई से जांच कराने पर सहमति दी। न्यायपालिका ने भी सीबीआई से जांच कराए जाने का आदेश किया। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस सीबीआई को सहयोग कर रही है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर घटना के विरोध में हड़ताल पर हैं। इस घटना की देशभर में प्रतिक्रिया हुई है। देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों मैं धरना प्रदर्शन और हड़ताल हुई। डयूटी डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की। पश्चिम बंगाल की इस घटना से पूरा देश उद्देलित है। इस घटना के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीति शुरू हुई है। नेशनल मीडिया इस घटना पर जिस तरह की कवरेज कर रहा है। उसने राजनीति को एक गेंगवार के स्वरूप में बदल दिया है। जिस तरह से एक गैंग दूसरी गैंग के इलाके में कब्जा करने के लिए सभी जायज और नाजायज तरीकों का उपयोग करते हुए अपना इलाका बढ़ाना चाहते हैं। ठीक वही स्थिति वर्तमान में पश्चिम बंगाल में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। भाजपा ने ममता बनर्जी और वाम दल को निशाना बनाकर आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों को ढाल बनाकर एक तरह से राजनीति की गेंगवार का हमला माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को अस्पताल में घुसकर भारी तोड़फोड़ की। वहां पर जिस तरह आतंक और दहशत का माहौल बनाया गया। वह आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। ममता बनर्जी राजनीति की इस गेंगवार में शुक्रवार को स्वयं प्रदर्शन करने सडकों पर उतरी हैं। उनका कहना है, सीबीआई जल्द से जल्द घटना की जांच करें। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। रही-सही कसर राज्यपाल सीबी आनंद ने आंदोलनकारियों के पास पहुंच कर पूरी कर दी है। राज्यपाल महोदय के ऊपर खुद ही महिला छेड़छाड़ के आरोप हैं। आंदोलनकारियों को संवैधानिक पद पर रहते हुए उकसाने का काम कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह न्यायपालिका और मीडिया का उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। न्यायपालिका और मीडिया के माध्यम से विपक्षियों पर हमला करने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल इसमें सबसे आगे है। भारत में वाम दल केडर बेस पार्टी है। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी का अपना कैडर है। अन्य दलों के पास ऐसा कोई कैडर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी और वाम दल आमने-सामने होते हैं। तो यह मुंबई की गैंगवार की तरह लड़ाई झगड़ा और हिंसा में परिवर्तित हो जाती है। पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल और कोलकाता में यही स्थिति देखने को मिल रही है। इस गैंगवॉर में जब न्यायपालिका और मीडिया लिप्त हो तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पडना तय है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच पर भाजपा ही संतुष्ट नहीं हैं? जो घटना कोलकाता में हुई है। उससे भी वीभत्स घटना बिहार के मुजफ्फरनगर में 12 अगस्त को हुई है। जहां पर एक नाबालिक लड़की के साथ अपहरण करके उसकी हत्या की गई। उसके गुप्तांग में 50 से अधिक चोट के निशान हैं। वहां डबल इंजन की सरकार है। सरकार और मीडिया चुप है। अन्य राज्यों में आए दिन इसी तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन वह घटनायें मीडिया में आकर गायब हो जाती हैं। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें नहीं है। उन राज्यों का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिये सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद जनता के पास एक ही विकल्प रह जाता है। जनता सड़कों पर आकर न्याय पाने की कोशिश करे। हाल ही में बांग्लादेश की सड़कों पर जनता उतरी। उसने अपने तरीके से विरोध करते हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। भारत में जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में इस घटना के बाद देखने को मिल रही है। वह जनता को बगावत और जन विद्रोह का रास्ता दिख रही है। राजनीतिक दलों की स्वार्थ सिद्धि के लिये जिस तरह के उन्ही दांव पेंच का उपयोग करते हैं। जोड़-तोड़, अंतर- विरोध के साथ प्रतिशोध की राजनीति अब गेंगवार के रूप में बदल गई है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हाल ही में 15 अगस्त को जब लाल किले से झंडा फहराया जा रहा था। उसमें भी प्रतिशोध की राजनीति का एक नया स्वरूप देखने को मिला। जब नेता प्रतिपक्ष जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्हें पांचवी पंक्ति में खिलाड़ियों और आमंत्रित अतिथियों के साथ बैठाकर, एक तरह से उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। सारा देश टीवी पर स्वतंत्रता के 78 वें वर्ष का समारोह देख रहा था। बहुदलीय लोकतंत्र में दलीय हितों का टकराव स्वाभाविक है। संवैधानिक मर्यादा, शिष्टाचार की परंपरा को तिलांजलि देना चिंता का विषय है। नागरिकों के मन में संविधान, लोकतंत्र, कानून और व्यवस्था का शासन है। यह अहसास होना जरूरी है। सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद करके रख रहा है। जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। उनको गिराने या अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता भी यथा राजा तथा प्रजा की तरह सड़कों पर आकर वही सब कर रही है, जो राजनेता और राजनैतिक दल कर रहे हैं। जनता को न्यायपालिका से कुछ आशा थी। अब ऐसा लगता है, कि न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। ठीक यही स्थिति बांग्लादेश की थीं। वर्तमान स्थिति में सभी राजनैतिक दलों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। अन्यथा आनेवाले समय में परिणाम भयानक होंगे।

मोदी जी का सेक्युलरज्म और हम-आप

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का लालकिले से ग्यारहवां उदबोधन बहुत महत्वपूर्ण रहा । महत्वपूर्ण दो कारणों से रहा ,पहला तो उन्होंने पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किये बिना एक्सटेम्पोर भाषण दिया। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया । वैसे तीसरा कारण भी है कि उन्होंने अब हमेशा के लिए जय हिन्द कहना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अब नेहरू की तरह नेताजी सुभासचन्द्र बोस भी पसंद नहीं हैं।

मै माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का अखंड समर्थक हूँ ,इसलिए मैंने उन्हें सुनने के लिए पूरे 98 मिनट खर्च किये। हालाँकि मेरे समय का कोई मोल नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि मोदी जी ने अपने भाषण में पहली बार सेक्युलर नागरिक संहिता की बात अपने मुखारविंद से कही। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब बार-बार सुना तो तब मानना पड़ा कि मोदी जी ही सेक्युलर शब्द बापर रहे हैं ,अन्यथा मोदी जी और उनके करोड़ों भक्त लगातार संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग करते रहे है। मोदी एंड कम्पनी का आरोप है कि संविधान मेंसेक्युलर शब्द था ही नहीं ,इसे तो बाद में जोड़ा गया है। अब संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने वालों का आभार मानना पडेगा मोदी जी को। क्योंकि यदि ये शब्द संविधान में न होता तो वे इसका इस्तेमाल कैसे करते ?

लालकिले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भाषण दे रहे थे लेकिन बार-बार भरम हो रहा था कि वे रामलीला मैदान में भाजपा की किसी चुनावी रैली को सम्बोधित कर रहे हैं न की राष्ट्र को। उनके सामने राष्ट्र जैसे था ही नहीं। वे अपने पुरखों को निशानेपर रखे हुए थे । उन्होंने कृपा इतनी की कि न नेहरू और इंदिरा गांधीका नाम लिया और न अटल बिहारी बाजपेयी जी का । वैसे वे लतिया सभी को रहे थे और अच्छा लतिया रहे थे। इस मामले में मोदी जी का लोहा मानना पडेगा। बांग्लादेश में भी देश के स्वतांत्रता सेनानियों को हाल में इसी तरह लतियाया गय। शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाएं भंग की गयीं। उनकी पार्टी के नेताओं की हत्या की गयी और उनकी बेटी को देश निकला दे दिया गया। गनीमत ये है कि हमारे यहां सियासी अदावत अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची है।

मोदी जी दुनियादारी के फेर में नहीं पड़े । उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ ज्यादती पर सिर्फ चिंता जताई लेकिन बांग्लादेश की नयी सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी । देते भी कैसे ? वे तो बांग्लादेश की नयी सरकार से भी दोस्ती बरकरार रखना चाहते है। ये अच्छी बात है। उन्हें बांग्लादेश से ही नहीं सभी पड़ौसियों से दोस्ती बनाकर रखना चाहिए ,अन्यथा अब कोई पड़ौसी दोस्त है ही कहाँ हमारा। प्रधानमंत्री जी ने भारत की विदेशनीति के बारे में दुनिया को कोई संकेत नहीं दिया। दुनिया निराश हो गयी। मोदी जी के भाषण में सब कुछ था लेकिन देश की जनता के लिए कुछ नहीं था,जो कुछ था वो विपक्ष के लिए था,अल्पसंख्यकों के लिए और अदालतों के लिए था। उनकी असली अदावत इन्हीं तीनों से है। मोदी जी ने सबसे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अतिथियों की पांचवीं कतार में बैठा दिया । उन्हें इससे सुख मिला होगा । हर आदमी अपने सुख के लिए ही दूसरे को अपमानित करता है ,अन्यथा राहुल गांधी के पास भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा है ,वे भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठाये जा सकते थे ,लेकिन ये संसद नहीं है ,जहां व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। सरकार की व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ,ये देशद्रोह है और इसके अलावा कुछ नहीं।

माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार बैशाखियों के सहारे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले उदबोधन में देश को क्या उपहार दिया ? ये हमें तो नहीं पता । आपको पता हो तो अवश्य शेयर कीजिये। डाक्टरों की 75 हजार सीटें जरूर बढ़ाई गयीं है ,लेकिन इसका लाभ गरीब जनता को मिलेगा या अमीर मेडिकल कालेज संचालकों को ,ये सोचना पडेगा। हमारी सरकार वैसे भी सबसे पहले यानि जनता से पहले अपनी जनता यानि ए -1,और ए -2 का ख्याल रखती आयी है। ये दोनों भी सरकार को वैसा ही समर्थन देते आ रहे हैं जैसा की टीडीपी या जेडीयू।

माननीय मोदी जी का भाषण अकेले हम ही नहीं देश के करोड़ों लोग सुनते है। कम से कम वे 85 करोड़ लोग तो सुनते ही हैं जिन्हें हमारी सरकार लगातार अनेक वर्षों से एक जून की रोटी मुफ्त में दे रही है ।इस भीड़ को लगता है कि मुमकिन है कि मोदी जी पंद्रह अगस्त को पांच किलो अन्न के साथ दाल और नमक भी मुफ्त देने की घोषणा करें ।

माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हमसे ज्यादा जानने वाले गोदी मीडिया का मानना है कि लालकिले से दिए गए उदबोधन का अर्थ है कि -यूसीसी को सेक्युलर कोड संहिता का नया कलेवर दिया जाएगा । भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, मतलब केजरीवाल जैसों पर कार्रवाई होती रहेगी। रिफॉर्म नहीं रुकेंगे। शिक्षा और रोजगार पर जोर जारी रहेगा और हिन्दू -मुसलमान होता रहेगा ।मुमकिन है की गोदी मीडिया आकलन हमसे ज्यादा सही हो ,इसलिए हम इससे इंकार भी नहीं करते। और इसीलिए हमेशा से माननीय मोदी जी कि सामने नतमस्तक रहते हैं

हमारे ऐसे ही एक श्रोता ने हमें आगाह किया कि मोदी जी लालक़िले से लगातार ग्यारह साल से मोदी जी सुभाष चन्द्र बोस का अपमान करते आ रहे हैं। आज़ाद हिन्द फ़ौज में अभिवादन के लिए जय हिन्द शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जो आज भी पुलिस, अर्द्ध सैनिक बलों और सेना में प्रचलन में है। इस यादगार को चिरस्थायी बनाने के लिए पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु लालक़िले से अपने उद्बोधन के बाद जयहिंद बोला करते थे जो माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक जारी रहा।लेकिन अब मोदी जी जय हिन्द नहीं कहते।

सवाल ये है की क्या मोदीजी जाने अनजाने लगातार सुभाष चन्द्र बोस जी अपमान करते जा रहे हैं। संभवत: वे अपने संघ के संस्कारों से इतने प्रभावित हैं कि जय हिन्द शब्द से नफ़रत करने लगे हैं।मोदी जी को शायद नहीं पता की आज़ाद हिन्द फ़ौज को मार्च का गीत भारतीय सेना ने अपनाया है। सुभाष चन्द्र बोस के हर योगदान को चिरस्थायी बनाया गया। मोदी जी नेहरू जी खिलाफ अभी तक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का इस्तेमाल करते थे ,लेकिन अब उन्हें भी नेहरू की तरह अपना अरि समझने लगे हैं ये हैरान करने वाले बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता की ये बात सही होगी। (लेखक - राकेश अचल/ ईएमएस)

महिला डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या से जुड़े

कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के दुराचार, बलात्कार व बर्बर हत्या पर स्वाभाविक ही देशभर के आमजन में तीखी प्रतिक्रिया एवं डॉक्टरों तीव्र रोष, गम और गुस्सा है, उसे समझा जा सकता है। जीवन-रक्षा करने वाले अस्पतालों एवं जीवन-रक्षक डाक्टरों पर हो रहे हमले, बर्बर एवं वीभत्स घटनाएं चिन्तनीय है। यह सरकारों एवं पुलिस की असफलता, लापरवाही एवं कोताही को ही दर्शा रही है। ऐसी घटनाओं में पुलिस की भूमिका अनेक सवाल खड़े कर रही है। कोलकाता की इस घटना ने एक बार फिर इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों को किस तरह के खतरों के बीच काम करना पड़ता है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर भी डरे एवं सहमे हुए हैं। लेडी डॉक्टर्स ही नहीं, पुरुष डॉक्टर भी तरह-तरह के हमलों की आशंकाओं एवं असुरक्षा के बीच जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि घटना के बाद भी पुलिस संतोषनक कार्रवाई नहीं कर सकी। डॉक्टरों की बुनियादी मांग यह है कि इस घटना की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित की जाए।

यह घटना दर्दनाक होने के साथ-साथ अमानवीयता एवं क्रूरता की पराकाष्ठा थी, क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बहने के अलावा उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिलने की बात कही गई है। इस त्रासद एवं खौफनाक घटना के विरोध में देशभर में गुस्साए और फिक्रमंद डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गयी हैं एवं सभी हिस्सों में ओपीडी सेवाएं बाधित एवं प्रभावित हो रहीं। जाहिर है, इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चूंकि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है और राज्य पुलिस को सारे कागजात बुधवार 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने की हिदायत दी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मामले की संतोषजनक जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अस्पतालों में सिर्फ डॉक्टर ही खतरे में होते हैं? डॉक्टरों के साथ नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं रोगी भी कहां सुरक्षित है? हालांकि हड़ताली डॉक्टरों ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को मुद्दा बनाया है, लेकिन नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले कभी इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनते? मसला मरीजों की सुरक्षा का भी है। 2024 में अस्पतालों में हुए यौन हमलों के हर पांच में से चार मामलों में पीड़ित महिला मरीज रही हैं। सवाल यह भी है कि अस्पतालों में ओवरचार्ज के रूप में मरीजों पर होने वाले वित्तीय हमलों को क्यों चर्चा से बाहर रखना चाहिए? आखिर अस्पतालों में बनते असुरक्षा के माहौल का यह भी एक अहम पहलू है। हमारे अस्पताल हर तरह से सुरक्षित होने चाहिए और इसके लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। संभवत: इसीलिए हड़ताली डॉक्टरों की एक प्रमुख मांग यह है कि हेल्थकेयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए देश में एक नया केंद्रीय कानून बनाया जाए।

बढ़ते डॉक्टरों पर हमलों के कारण उनका डर और उनकी चिंता जायज है। लेकिन जहां तक केंद्रीय कानून की मांग है तो सवाल यह है कि क्या कोलकाता में लेडी डॉक्टर पर हुआ हमला कड़े कानूनों की कमी का परिणाम माना जा सकता है? सच यह है कि ज्यादातर राज्यों में मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स और मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा या क्षति या संपत्ति के नुकसान की रोकथाम) अधिनियम पहले से ही लागू है। अब तो हर अस्पताल में डाक्टरों पर हमलों के लिये चेतावनी के बोर्ड देखने को मिलते है कि ऐसी घटनाओं को अपराध मानते हुए उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मगर इन राज्यों में भी इसके तहत दर्ज मामलों में दस फीसदी ही आरोप तय होने के बाद अदालत तक पहुंच पाते है। जाहिर है, मूल समस्या कानून में नहीं, उस पर अमल में है। अदालत ने उचित ही आंदोलित डॉक्टरों को उनके पवित्र एवं पावन दायित्व का एहसास कराया है और उनसे अपने काम पर लौटने की अपील की है। आखिर किसी जालिम की करतूत की सजा बेकसूर मरीजों को क्यों मिलनी चाहिए? इसलिये न्याय मांगते डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि इंसाफ का तकाजा क्या यह भी नहीं है कि किसी मरीज से नाइंसाफी न हो?

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, 75 प्रतिशत से अधिक डॉक्टरों को काम पर हिंसा का सामना करना पड़ता है। तूतीकोरिन में एक महिला डॉक्टर की हत्या एक गर्भवती महिला के पति ने की थी, जिसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन उसे स्थानांतरित किए जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पति ने तीन साथियों के साथ महिला डॉक्टर के परामर्श कक्ष में प्रवेश किया और उस पर तलवार से हमला किया। 2014 में, पंजाब के मनसा जिले में एक लड़के की मौत के बाद एक डॉक्टर के क्लिनिक को जला दिया गया था, जिसे तृतीयक अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। भारत भर में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की असंख्य घटनाएं लगभग हर दिन सामने आती हैं, जिनमें से कुछ में गंभीर चोटें भी आती हैं। यहां तक कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली जैसे संस्थान भी इससे अछूते नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में बात केवल राजनीतिक हिंसा एवं आक्रामकता की ही नहीं है बल्कि कुशासन एवं अराजकता की भी है। वहां आमजनता के साथ साथ अस्पतालों की सुरक्षा भी खतरे में है। इसका एक उदाहरण चुनाव से पहले कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10 जून की रात को सामने आया था, वह भी एक काला अध्याय ही था। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग मरीज की मृत्यु के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों ने डॉक्टरों पर हमला बोल दिया था, जिससे कई डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारत में डॉक्टर को लगभग भगवान का दरजा मिला हुआ है। ऐसे में, आमतौर से उन पर हमला किसी ऐसे निरंकुशता और असंवेदनशीलता की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जो तंत्र से पोषित एवं संरक्षित होता है। उसकी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, पर इसे किसी शून्य की उपज भी नहीं कह सकते। लेकिन ताजा घटना में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसने तो सारी सीमाएं लांघ दी है।

इस हत्याकांड ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार एवं पुलिस-प्रशासन को सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया है। खुद अदालत ने सवाल किया कि आखिर शुरुआत से ही हत्या के बजाय अस्वाभाविक मौत के नजरिये से जांच क्यों की गई? फिर 9 अगस्त को घटी इस घटना में उसने जिस आरोपी को हिरासत में लिया है, वह एक पुलिस का वॉलंटियर बताया जाता है और उसे इस अस्पताल में अक्सर मंडराते देखा जाता था। इतने संवेदनशील मामले में अतिरिक्त सक्रियता बरतकर कोलकाता पुलिस न सिर्फ पीड़ित परिवार के भरोसे का संरक्षण कर सकती थी, बल्कि डॉक्टरों को भी यह यकीन दिला सकती थी कि अपराधी चाहे कोई भी हो चंद घंटों के भीतर वे सलाखों के पीछे होंगे! मगर बंगाल पुलिस ने कहीं न कहीं कोताही बरती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उसे यह अल्टीमेटम देना कि रविवार तक जांच पूरी हो, वरना मामला सीबीआई को सौंप देंगे, आखिर क्या ध्वनित करता है? दरअसल, यह सिर्फ एक राज्य की पुलिस की बात नहीं है। लोगों की निगाहों में राज्य-दर-राज्य पुलिस की छवि इतनी कमजोर हो चली है कि जघन्य अपराधों की जांच में भी लोग उसकी पेशेवर काबिलियत पर आसानी से भरोसा नहीं करते और उसमें राजनीतिक कोण देखने लगते हैं। निस्संदेह, इसके लिए पुलिस के साथ-साथ राजनीतिक नेतृत्व भी बराबर के दोषी हैं। सीबीआई की कार्यशैली भी सवालों से घिरी हैं ऐसे में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के हत्याकांड की जांच उसके लिए एक नई चुनौती है कि वह जल्दी से जल्दी इसकी जांच मुकम्मल कर न सिर्फ दोषी या दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं, बल्कि अपनी छवि भी सुधारे। प्रेषक: (लेखक – ललित गर्ग/ ईएमएस) (लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर के सभी चुनाव एक साथ....?

('वन नेशन: वन इलेक्शन')

प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार पुन: अपनी सरकार का यह संकल्प दोहराया कि देश में स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएगें और यह प्रक्रिया पांच साल बाद अर्थात् 2029 के चुनावों से शुरू कर दी जाएगी। केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी यही घोषणा पहले भी कर चुके है, अर्थात् अब यह सरकार इस देश में साल भर तक चलते रहने वाले विभिन्न चुनावों पर खर्च होने वाली भारी धनराशि और समय से मुक्ति दिलाने की ओर अग्रसर है, यद्यपि देश की आजादी के बाद पच्चीस से भी अधिक वर्षों तक एक साथ चुनाव कराने की ही प्रक्रिया जारी थी, जो 1971 तक चली बाद में फिर देश में विभिन्न स्तर के चुनाव उनकी कालावधि के अनुसार अलग-अलग सम पर होने लगे, अब प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार कर देश में फिर से सभी चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि पांच साल बाद अर्थात् 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों के समय पूरे देश की विभिन्न संस्थाओं के चुनाव भी करा लिए जाएगें और इसके लिए बाकायदा संसद से कानून में संशोधन करावाकर तैयारी पूरी की जाएगी। सरकार की दलील है कि इस प्रक्रिया के लागू होने से देश को चुनावों पर खर्च होने वाले करोड़ों रूपए की बचत के साथ समय की भी बचत होगी और फिर चुनी हुई सरकारें पूरे मनोयोग से जनहित के फैसले ले सकेगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि देश में हरसमय किसी न किसी संस्था या जनसंस्थओं के चुनाव चलते रहते है, इसके कारण सरकार पूरे मनोयोग से जनहितैषि योजनाओं पर ध्यान नही दे पाती और पांच साल की अवधि में सिर्फ एक या दो साल ही ठीक से सरकार चल पाती है, बाकी समय चुनावी तिकड़मों में नष्ट हो जाता है, इन्हीं सब कारणों से मोदी सरकार यह फैसला लेने जा रही है, जिसका उन्होंने आज अपने स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में जिक्र किया।

इस समस्या का समाधान खोजने के लिए मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था, जिसने विगत 14 मार्च को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट केन्द्र राष्ट्रपति को सौंपी है, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 'एक देश-एक चुनाव' के प्रस्ताव पर समिति ने 62 राजनीतिक दलों से चर्चा की, जिसमें से 32 दलों ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जबकि पन्द्रह राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, इस तरह 47 दलों ने ही इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, शेष दलों ने अभी तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने संसद में दी।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाली केन्द्र सरकार का कहना है कि यदि देश के सभी चुनाव एक साथ करवा लिए जाए तो चुनाव जीतने वाले दलों की संस्थाऐं पूरे पांच साल बिना किसी अवरोध के जनहित के कार्य पूरे कर सकती है, उसे किसी भी तरह की अड़चन पैदा नही होगी, वह अपने चुनावी घोषणा पत्र को मूर्तरूप दे सकेगी, जबकि मौजूदा हालातों में चूने हुए दलों व उनकी संस्थाओं का काफी समय व पैसा प्रचार व अन्य कार्यों पर खर्च हो जाता है और यह राशि करोड़ों अरबों में होती है, यदि इस राशि को किसी भी तरीके से बचा लिया जाता है तो यह राशि जनहित के अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च की जा सकी है साथ ही चुनावों पर खर्च होने वाली राशि से अन्य कार्य भी सम्पन्न हो सकते है, इसीलिए मोदी सरकार के साथ राज्यों की भाजपा सरकारें इस पर गंभीर चिंतन कर चूकी है।

....और कोई आश्चर्य नहीं कि केन्द्र सरकार अपने स्तर पर तथा अपनी भाजपा राज्य सरकारों से राज्य स्तर पर इस योजना को शीघ्र मूर्तरूप दे दें, इसलिए देश की जनता को भी प्रति पांच वर्ष में 'चुनावी पर्व' मनाने के लिए मानसिक तथा व्यवहारिक रूप से अपने आपको तैयार करना होगा। (लेखक- ओमप्रकाश मेहता/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8100

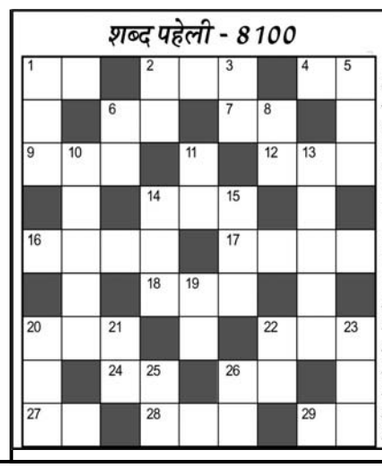

बाएँ से दाएँ

1.भीगा हुआ-2
2.गाने वाला-3
4.दिया, चिराग-2
6.केश-2
7.जिससे ताला खुलता है-2
9.सूरमा -3
12.नख-3
14.तेरह गुणा चार-3
16.एक जैसा तल-4
17.दरवाजे की आवाज-2,2
18.कड़ा, तेज-3
20.आँखों के ऊपर की परत-3
22.साधुवाद देना,वाह-वाह-3
24.पुत्र, एक रंग-2
26.तुम का आदर सूचित शब्द-2
27.पत्र-2
28.आश्चर्य-3
29.तट, किनारा-2

ऊपर से नीचे

1.छोटा गीत-3
2.मुँह के दोनों ओर का भाग-2
3.जो पका न हो-2
5.हवा, वायु-3
6.बच्चा, बालक-2
8.वीणा, एक वाद्य-2
10.जितेन्द्र व रेखा की एक फिल्म-2,3
11.मूल्य, दर-2
13.मारकाट-5
14.बच्चा-3
15.नाज, अदा-3
19.पंजाब की एक नदी-2
20.जांच-पड़ताल-3
21.हुनर-2
22.बददुआ-2
23.नगर-3
25.बेल, कोमल लम्बा पौधा-2
26.फूलों का प्राकृतिक रस-2

शब्द पहेली-8099 का हल

त	मा	शा	ई	■	ह	जा	म	त
ल	ता	■	मा	ज	रा	■	त	ह
वा	■	■	न	■	र	न	■	री
र	ह	न	■	न	त	म	स्त	क
■	■	शे	■	य	■	की	■	■
ना	मु	म	कि	न	■	न	मा	ज
वा	■	न	पा	■	स	■	■	रु
कि	म	■	य	म	न	■	द	र
फि	त	र	त	■	क	रा	मा	त

Jagrutidaur.com, Bangalore

चंदा देने पर 12 साल की कैद

मास्को(ईएमएस)। रूस में एक महिला को 12 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। उसने यूक्रेन से जुड़ी एक चैरिटी संस्था रजोम को 50 डॉलर (करीब 4200 रुपए) चंदा दिया था। महिला का नाम कसेनिया खवाना (33) है। उसके पास अमेरिकी नागरिकता है। कसेनिया को इस साल फरवरी में रूसी शहर येकातेरिनबर्ग से गिरफ्तार किया गया था। यह मॉस्को से 1600 किमी दूर पूर्व में स्थित है। यहां वह अपनी दादी से मिलने आई थी। शादी से पहले उसका नाम कसेनिया कैरिलिना था।

खेल - समाचार

डेवोन कॉनवे और फिन एलन ने ठुकरा दिया केंद्रीय अनुबंध को

नई दिल्ली (ईएमएस)। हाल ही में न्यूजीलैंड के केंद्रीय अनुबंध को स्टार कीवी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे और फिन एलन ने ठुकरा दिया है। कीवी खिलाडियों ने श्रीलंका के सफेद गेंद के मैचों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए खुद को उपलब्ध रखा है, क्योंकि वह एसए20 में हिस्सा लेंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार एलन बिग बैश लीग अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कॉनवे कीवी के सभी नौ आगामी लंबे प्रारूप मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे और उन्होंने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अभ्यास मैचों के लिए प्रतिबद्धता जताई है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आगामी आईसीसी से पहले एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला खेलेगा। कॉनवे ने इस प्रक्रिया के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अनुबंध से बाहर निकलने का फैसला कोई आसान फैसला नहीं था।उन्होंने कहा, सबसे पहले, मैं इस प्रक्

बाजार गुलजार... सेंसेक्स 1330 अंक उछला, निफ्टी 24500 के ऊपर बंद हुआ

निवेशकों को 7.17 लाख करोड़ का फायदा

मुंबई(ईएमएस)। बैंकिंग और आईटी शेयरों में मजबूती के कारण घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 30 शेयरों का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 1,330.96 (1.68 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ 80,436.84 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 397.41 (1.65 प्रतिशत) अंक उछलकर 24,541.15 के स्तर पर बंद हुआ।भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दो सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। आईटी शेयरों और रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी और वैश्विक शेयरों में तेज के बाद बाजार में मजबूती आई। सेंसेक्स दिन के कारोबार के दौरान 1,412.33 अंक या 1.78 प्रतिशत बढक़र 80,518.21 के स्तर पर पहुंचा। शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 7.17 लाख करोड़ रुपये बढक़र 451.46 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सेंसेक्स की कंपनियों में से टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा स्टील सबसे ज्यादा लाभ में रहीं। एकमात्र सन फार्मा के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सभी क्षेत्रीय सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। बीएसई मिडकैप में 1.8 फीसदी की तेजी आई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.7 फीसदी की तेजी आई। एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग में काफी तेजी रही। यूरोपीय बाजार ज्यादातर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी बाजार तेज बढ़त के साथ बंद हुए।जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, जेपीवाई की स्थिरता वैश्विक बाजार में सुधार लाने में सहायक रही है। इसके अलावा, मजबूत अमेरिकी खुदरा बिक्री और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों में गिरावट ने अमेरिकी मंदी की आशंकाओं को कम करने में मदद की है।

इसके अलावा, अमेरिकी सीपीआई मुद्रास्फीति में कमी के कारण बाजार की धारणा में सुधार हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में, भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी दिखी। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने इससे पहले बुधवार को 2,595.27 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,236.21 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.22 प्रतिशत गिरकर 80.05 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बंद रहे। बुधवार को बीएसई बेंचमार्क 149.85 अंक या 0.19 प्रतिशत चढक़र 79,105.88 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,143.75 पर बंद हुआ था।

ये 10 शेयर बने रॉकेट

सबसे ज्यादा तेजी हाल ही लिस्ट हुई कंपनी ओला इलेक्ट्रीक के शेयरों में देखा गया, जिसने आज 20 फीसदी का अपर सर्किट लगाया है। लॉन्ग टर्म में डीएलएफ के शेयर 5 प्रतिशत, विप्रो के शेयर 4.26 प्रतिशत, पॉवर फाइनेंस कॉर्प 4 फीसदी, पॉलिसी बाजार के शेयर 8 फीसदी, पीरामिल एंटरप्राइजेज 7.36 प्रतिशत, एमपैसा 7 प्रतिशत, सीडीएसएल के शेयर 9 फीसदी, जेन्सर टेक्नोलॉजी 7.73 प्रतिशत और निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी 7.49 प्रतिशत चढ़ गया।

52 सप्ताह के हाई पर 95 शेयर

एनएसई के कुल 2,797 शेयरों में से 1,872 शेयरों में उछाल देखी जा रही है। वहीं 845 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा, 80 शेयर अनचेंज रहे। 95 शेयर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर थे, जबकि 31 शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। 112 शेयर अपर सर्किट और 76 शेयर लोअर सर्किट पर थे।

हिजाब ना पहनने पर महिला को गोली मारी

तेहरान(ईएमएस)। ईरान में हिजाब ना पहनने के आरोप में महिला को गोली मारनेका मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22जुलाई को पुलिस ने हिजाब ना पहनने के आरोप में महिला की कार को रोकने का प्रयास किया। जब वह गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करने लगी तो पुलिस ने महिला पर गोली चला दी।

महिला का नाम अरेजू बद्री है, जिसकी उम्र 31 साल है। वह 2 बच्चों की मां है। गोली लगने से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह लकवाग्रस्त है। दूसरी तरफ, पुलिस ने बताया कि गश्त कर रहे अधिकारियों ने महिला को गाड़ी को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि पुलिस ने अपने बयान में हिजाब ना पहनने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है।

ईरान में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के कार्यकारी निदेशक हादी घामी ने घटना पर कहा कि,ईरान में हिजाब ना पहनने को सबसे गंभीर अपराध बना दिया है। जहां पुलिस को गोली मारकर हत्या करने की अनुमति है। यह वास्तव में महिलाओं के खिलाफ युद्ध जैसा है।

चीन से मिले फाइटर जेट पर इतरा रहा पाकिस्तान.....भारत से 12 साल आगे

नई दिल्ली (ईएमएस)। पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद तेजी से अपनी फ्लीट को आधुनिक करने में जुटी है। चीन से लगातार नए-नए फाइटर जेट्स खरीद रही है। इस बीच पीएफए यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर कोमोडोर जिया उल हक शम्सी का बयान सामने आया है, इसमें उन्होंने शेखी दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना वर्तमान में भारतीय वायुसेना से 12-14 साल आगे निकल चुकी है।

एयर कोमोडोर जिया उल हक ने कहा कि इसकी वजह है चीन से खरीदा गया एफसी-31 स्टेल्थ फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास अब पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी फाइटर जेट नहीं है। यह चीन का मल्टीरोल स्टेल्थ फाइटर है, जो भारत को परेशान कर सकता है।

पाकिस्तान ने चीन से कितने जे-31 फाइटर जेटर खरीदे हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन भारत के पास फिलहाल स्टेल्थ फाइटर जेट छोड़िए, पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं है। भारत के पास चौथे और 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट्स का मिश्रण है। जिसमें राफेल और तेजस सबसे नए हैं।

पाकिस्तान के प्लेन की तुलना भारत के एएमसीए यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से हो रही है। एएमसीए प्रोजेक्ट अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बनाकर आने में करीब 11 साल और लगाने वाले है। सेना में शामिल होने में 2-3 साल और मान लीजिए। इस हिसाब से एयर कोमोडोर हक की बात सही लगती है।

भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी का कोई फाइटर जेट नहीं है। भारत में अभी एएमसीए फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इस बनकर आने में अभी कुछ साल बाकी हैं। एक बार यह फाइटर जेट बन गया, तब भारत पाकिस्तान पर ज्यादा भारी पड़ेगा। क्योंकि इसकी गति 2600 किलोमीटर/ प्रतिघंटा रहेगी। इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर और पूरी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। यह अधिकतम 65 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा।

कई मामलों में भारतीय पाकिस्तानी एयरफोर्स से कई गुना आगे

अगर फ्लीट, अनुभव, ताकत, और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भारतीय वायुसेना आज भी पाकिस्तानी एयरफोर्स से कई गुना आगे हैं। भारतीय वायुसेना का फोकस फिलहाल नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर है। लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक पर है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर है। ये तीनों ही पाकिस्तान के जे-31 का खतरा खत्म कर देने वाले है।

भारत के पास अभिनंदन का उदाहरण

जे-31 के जरिए आसमानी जंग में पाकिस्तान को तकनीकी बढ़त है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि उसके पास नया और आधुनिक विमान हो तब ताकतवर है। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पुराने मिग-21 बाइसन फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एफ-16 फाइटर जेट को मार गिराया था।

चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने एफ-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते। वे चीन से ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं। 2012 से लेकर 2019 तक इसमें कई बार डिजाइन में बदलाव किए गए। टेस्ट फ्लाइट्स हुईं। इस एक ही पायलट उड़ाएगा। 56.9 फीट लंबे इस लड़ाकू विमान की ऊंचाई 15.9 फीट है।

टेकऑफ के समय अधिकतम वजन 2800 किलोग्राम रहता है। यह अधिकतम 2205.08 किलोमीटर/ प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस जेट की कॉम्बैट रेंज यानी हथियारों के साथ यह 1200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हवा में रीफ्यूलिग होने पर 1900 किलोमीटर तक आसानी से आ-जा सकता है। अधिकतम 52 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।

इस फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्डप्वाइंट्स हैं। जिसमे कुल मिलाकर 10 हजार किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें, हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें लगा सकते हैं। इसमें 500 किलोग्राम वजन के 8 डीप-पेनेट्रेशन बम लगा सकते हैं।

बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया

ढाका(ईएमएस)। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। मोदी ने बातचीत को लेकर ङ्ग पर पोस्ट किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं। अब तक हिंदुओं पर हमले के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं।

हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंतित

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के हाईकमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के एडवाइजर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश में वीजा फैसिलिटी को पूरी तरह कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश में वीजा पर सख्ती लागू रहेगी। हालांकि, बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर सुविधाएं दी जा रही हैं।

फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40 हजार पहुंचा -18 लाख लोग बेघर

गाजा(ईएमएस)। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में मरने वाले फिलिस्तीनियों लोगों का आंकड़ा 40 हजार के पार हो गया है। वहीं गाजा पर इजराइली हमलों में अब तक 90 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी किए आंकड़ों में हमास के आतंकवादियों को भी शामिल किया गया है। मरने वालों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अभी भी कई शव मलबे में दबे हुए हैं। गाजा में 11 महीनों से जारी है जंग

इजराइल और हमास बीच इस जंग को लगभग 11 महीनों का वक्त बीत गया है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में लगभग 1200 इजराइली नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं आंतकवादी लगभग 250 लोगों बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इजराइल के मुताबिक अभी भी 111 लोग हमास की कैद में मौजूद है। इनमें 39 शव भी शामिल हैं। बंधकों में 15 महिलाएं और 5 साल से कम उम्र के 2 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस जंग में अब तक इजराइल के 329 सैनिकों की भी मौत हो गई है। वहीं इजराइली सेना के मुताबिक उन्होंने अब तक हमास के 15 हजार से अधिक आतंकियों का मार गिराया है। जंग की वजह से गाजा में लगभग 18 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इजराइल और दक्षिणी लेबनान में भी हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।

5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट

जंग की वजह से गाजा में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इजराइली हमलों की मार झेल रहे गाजा के नागरिकों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लगभग 5 लाख लोगो को आने वाले महीनों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। ये आंकड़ा गाजा की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।

गाजा में सीजफायर के लिए कतर में बातचीत

इजराइल- हमास के बीच सीजफायर और बंधकों की अदला-बदली के लिए कतर में 15 अगस्त से बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत दो दिन चलेगी। इस सीजफायर डील में इजराइल के अलावा कतर, अमेरिका और मिस्त्र के नेताओं ने हिस्सा लिया। हमास की कोई भी प्रतिनिधि इस बातचीत में शामिल नहीं हुआ। इस डील के लिए पिछले दो महीने से ज्यादा समय से कोशिश चल रही थी। डील के तहत गाजा में 3 फेज में सीजफायर लागू करने का प्लान है। इस प्लान के मुताबिक हमास 7 अक्टूबर को बंधक बनाए कुछ लोगों को रिहा करेगा। साथ ही इजराइली सेना गाजा के इलाके से पीछे हटेगी। इसके अलावा इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा।

इजराइल पर ईरानी हमले का खतरा

पिछले महीने 31 जुलाई को ईरान में हमास चीफ हानियेह की मौत के बाद से इजराइल पर ईरानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने हानियेह की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजराइल से बदला लेने का आदेश दिया था। इजराइल पर ईरानी हमले की बढ़ती आशंका के कारण अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पनडुब्बियों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 5 देशों के प्रमुख नेताओं की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में ईरान से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए कहा है।

शिनावत्रा थाइलैंड की पीएम बनी

बैंकॉक(ईएमएस)। थाइलैंड में संसद ने पाइतोंग्तार्न शिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनवात्राकी बेटी है। 37 वर्षीय पाइतोंग्तार्न देश की 31वीं प्रधानमंत्री बनी हैं। वे थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं, साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं।

यिंगलुक थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थीं। वह पाइतोंग्तार्न की बुआ हैं। पाइतोंग्तार्न, शिनवात्रा फैमिली से प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी नेता हैं। थाक्सिन के जीजा सोमचाई वोंगसावत भी 2008 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। थाक्सिन 2001 में थाइलैंड के पीएम बने थे। थाक्सिन शिनवात्रा को तख्तापलट के जरिए सत्ता से बाहर किया गया था। पाइतोंग्तार्न सत्ताधारी पार्टी 'फु थाई' की नेता है। हालांकि पाइतोंग्तार्न अभी सांसद नहीं हैं।

पाकिस्तान में मुठभेड़में टी टीपी के सात आतंकी ढेर

इस्लामाबाद,(ईएमएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के सात आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि कुर्रम जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली उसके आधार पर उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों ने टीटीपी के सात आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि पांच आतंकी घायल हुए हैं। बयान के मुताबिक आतंकवादियों के ठिकाने का भी भंडाफोड़ हुआ है और वहां से काफी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किया गया है।

सोना 70,350 रुपए, चांदी लगभग 82 हजार

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। सोने-चांदी के वायदा कारोबार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिल रही है। दोनों के वायदा भाव शुक्रवार को तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 70,350 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 82,000 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव तेज शुरुआत के बाद सुस्त पड़ गए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 167 रुपये की तेजी के साथ 70,303 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 231 रुपये की तेजी के साथ 70,367 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 1,438 रुपये की तेजी के साथ 81,499 रुपये पर खुला। इस समय यह 1,979 रुपये की तेजी के साथ 82,040 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी की शुरुआत तेजी के साथ हुई। हालांकि बाद में इनके भाव सुस्त पड़ गए। कॉमेक्स पर सोना 2,494.39 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,492.40 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 2.20 डॉलर की गिरावट के साथ 2,490.20 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 28.42 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 28.41 डॉलर था। इस समय यह 0.19 डॉलर की गिरावट के साथ 28.23 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

यूक्रेन-रूस में शांति लाने के भारत के प्रयासों का स्वागत करेगा अमेरिका

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति लाने के भारत के प्रयासों का स्वागत किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि इस महीने के आखिर में पीएम नरेन्द्र मोदी की संभावित यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि हम अनेक मुद्दों पर अपने भारतीय साझेदारों के साथ संपर्क में हैं और निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान भारत की बातचीत का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

यूपीआई के नए फीचर में एक ही बैंक खाते से दो लोग कर सकते हैं भुगतान

मुंबई (ईएमएस)। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर पेश किया है, जिससे ग्राहक अपने यूपीआई अकाउंट्स को दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई सर्कल डेलिगेट पेमेंट्स एक ऐसा फीचर है जिसमें यूपीआई अकाउंट का मास्टर एक्सेस अकाउंट होल्डर के पास रहता है लेकिन वह किसी और को भी भुगतान करने के लिए अकाउंट का एक्सेस दे सकता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल बैंकिंग संचालन के एक व?रिष्ठ अ?धिकारी का कहना है कि यह फीचर परिवार के सदस्यों या परिचितों को भुगतान करने का अधिकार सौंपने का एक नया तरीका है। इसके जरिए दो व्यक्ति एक ही बैंक खाते से यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। इस फीचर के तहत प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर के लिए एक मेन्डेट बना सकता है। प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर को पूरी या आंशिक रूप से भुगतान करने का अधिकार दे सकता है। यदि पूरा अधिकार दिया जाता है, तो सेकेंडरी यूजर को प्राइमरी यूजर द्वारा निर्धारित राशि का सीधे भुगतान करने का अधिकार होगा। आंशिक अधिकार की स्थिति में, सेकेंडरी यूजर को हर लेनदेन के लिए प्राइमरी यूजर से अनुमति का अनुरोध करना होगा। प्राइमरी यूजर सेकेंडरी यूजर के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट भी सेट कर सकता है। एनपीसीआई के मुताबिक पूरे अधिकार पर अधिकतम मासिक सीमा 15,000 रुपए होगी। आंशिक डेलीगेशन के लिए मौजूदा यूपीआई सीमा लागू होगी।

देश के 42 शहरों में 2,000 आवासीय परियोजनाएं अटकीं: प्रॉपइक्विटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के 42 शहरों में 5.08 लाख इकाइयों के साथ लगभग 2,000 आवासीय परियोजनाएं रुकी हुई हैं। डेटा एनालिटिक्स कंपनी प्रोपइक्विटी के अनुसार इसकी मुख्य वजह डेवलपर्स द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन और क्रियान्वयन क्षमताओं की कमी है। प्रोपइक्विटी के आंकड़ों के अनुसार, 1,981 आवासीय परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जिन में घरों की कुल संख्या 5.08 लाख है। इन रुकी हुई परियोजनाओं में से 1,636 परियोजनाएं 14 पहली श्रेणी के शहरों में हैं, जिनमें 4,31,946 इकाइयां रुकी हैं। जबकि 345 परियोजनाएं 28 दूसरी श्रेणी वाले शहरों में हैं, जिनमें 76,256 इकाईयां हैं। इसमें यह भी बताया गया कि रुकी हुई इकाइयों की संख्या बढ़कर 5,08,202 हो गई है, जो 2018 में 4,65,555 इकाई थी। प्रॉपइक्विटी के एक व?रिष्ठ अ?धिकारी ने कहा ?कि रुकी हुई परियोजनाओं की समस्या और उसके बाद उनमें वृद्धि, डेवलपर्स की निष्पादन क्षमताओं की कमी, नकदी प्रवाह के कुप्रबंधन और नए भूखंड खरीदने या अन्य कर्ज चुकाने के लिए धन के उपयोग के कारण है।

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर मिल रहा 7.4 फीसदी ब्याज

नई दिल्ली (ईएमएस)। पोस्ट ऑफिस हर आयुवर्ग के लिए कई तरह की सेविंग स्कीम संचालित कर रहा है। सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के मामले में भी ये स्कीम्स लोक?प्रिय है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (एमआईएसए) ज्यादा लोक?प्रिय है, इसमें एकमुश्क निवेश के बाद अगले महीने से ही ब्याज से कमाई होने लगती है। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी को देखें तो इस स्कीम में निवेश पर सरकार की ओर से शानदार 7.4 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर किया जाता है। एमआईएस में आपको अकाउंट खुलवाने की तारीख से एक महीना पूरा होने के बाद ही ब्याज का फायदा मिलना शुरू हो जाता है यानी निवेश के अगले महीने से ही नियमित आय की गारंटी वाली है, ये सरकारी स्कीम में आपको जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान मंथली किया जाता है।

आप महज 1,000 रुपये के निवेश के साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें अकाउंट दो तरीके से खोला जा सकता है, पहला सिंगल और दूसरा ज्वाइंट अकाउंट. अगर मैक्सिमम इन्वेस्ट लिमिट की बात करें, तो सिंगल अकाउंट होल्डर इस स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जबकि ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराने पर अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम के तहत निवेश करने के लिए पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी है। कोई भी 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है।

बांग्लादेश ने 7 देशों से राजदूत बुलाए

ढाका(ईएमएस)। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, जापान, जर्मनी, यूएई और मालदीव में तैनात अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन्हें शेख हसीना के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। बांग्लादेश में 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के गठन के बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर 7 देशों के राजदूतों को वापस बुलाने से जुड़ी अलग-अलग नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि राजदूतों और उच्चायुक्तों का ढाका ट्रांसफर कर दिया गया है। इन्हें मौजूदा जिम्मेदारी छोडक़र ढाका वापस लौटने का आदेश दिया गया है।

मिजोरम सरकार 50 लाख तक बिना ब्याज लोन देगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर मिजोरम सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि राज्य सरकार योग्य लोगों को फाइनेंशल ग्रोथ और जीवन यापन में सुधार के मद्देनजर 50 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराने के लिए योजना शुरू करेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबंधोति करते हुए मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि हमारी सरकार समावेशी शासन के अलावा राज्य की ग्रोथ, सरकारी प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ ही आम सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए के अपने लक्ष्य पर दृढ़ है। बीते साल दिसंबर 2023 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के बाद जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार ने कई बदलावों पर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और इसकी क्रम में एक बड़ा कदम उठाते हुए लोन स्कीम भी शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के जरिए सरकार आर्थिक विकास के लिए कदम आगे बढ़ाने वाले योग्य लोगों की की मदद करने के लिए गारंटर के रूप में काम करेगी। सीएम ने कहा कि मिजोरम सरकार गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे कि पात्रों को 50 लाख रुपये तक का लोन मिल सके और इसमें सरकार गारंटी देने के साथ ही ब्याज भी भरेगी।

सेंट मार्टिन नहीं.....करीब 700 से 1 हजार द्वीप मौजूद है बांग्लादेश में

ढाका (ईएमएस)। विदेशी मीडिया में इसतरह की खबरें हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता केवल एक द्वीप के कारण चली गई। इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इसका कुल एरिया महज तीन वर्ग किमी है। क्योंकि यह देश में तख्ता-पलट का कारण बना, इसकारण चर्चा में है। दरअसल बांग्लादेश में काफी बड़ी संख्या में द्वीप मौजूद हैं। इनकी संख्या 700 से 1000 के करीब होगी। इसमें बसे हुए और निर्जन दोनों तरह के द्वीप शामिल हैं। उल्लेखनीय द्वीपों में भोला सबसे बड़ा और सेंट मार्टिन बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा (कोरल) द्वीप है। बांग्ला देश में ज्यादातर द्वीप बंगाल की खाड़ी और पद्मा नदी के मुहाने पर स्थित हैं।

सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर- पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इसका कुल एरिया केवल तीन वर्ग किमी है। यह कॉक्स बाजार से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस द्वीप को बांग्लादेश में नारिकेल जिंजिरा (नारियल द्वीप) या दारुचिनी द्वीप (दालचीनी द्वीप) के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है। यह द्वीप विशेष रूप से सर्दियों में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस द्वीप पर रहने वाले लोग मुख्यत: मछली पकड़ने, चावल-नारियल की खेती और पर्यटन पर निर्भर हैं। यहां की कुल जनसंख्या करीब 5,000 है। इस द्वीप पर अधिकार को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद था। लेकिन 2012 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में द्वीप पर बांग्लादेश का अधिकार माना।

इस तरह एक और महत्वपूर्ण द्वीप हटिया है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह द्वीप भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। हटिया द्वीप अपनी कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है, जो नोआखली जिले का हिस्सा है। हटिया अपने मछली पकड़ने के उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।

सैंडविप द्वीप चटगांव के पास मौजूद है। यह मछली पकड़ने और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये द्वीप न केवल पर्यटन, मछली पकड़ने और कृषि के माध्यम से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि क्षेत्र में पारिस्थितिक और भू-राजनीतिक महत्व भी रखता है। बांग्लादेश में 26 से अधिक द्वीपों को मान्यता मिली हुई है और वे सूचीबद्ध हैं। लेकिन बहुत से छोटे द्वीप हैं, जिन्हें चार कहा जाता है। ये डेल्टा क्षेत्र में तलछट जमा होने के कारण बनते और बिगड़ते रहते हैं।

बांग्लादेश में जो बड़ी संख्या में द्वीप मौजूद हैं, उन्हें 'चार' कहा जाता है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, यह सटीक ढंग से नहीं कहा जा सकता है। चार' शब्द का प्रयोग उन तलछट द्वीपों के लिए किया जाता है, जो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के किनारे विकसित होते हैं। इन 'चार' को बाढ़, कटाव और भूमि के नुकसान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। चार' लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। जिससे खेती के लिए नए क्षेत्र बनते रहते हैं।

हसीना और नौ अन्य लोगों के खिल

कोलकाता मामले के बाद

आज से गुजरात के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और वार्ड सेवाएं बंद हैं

गांधीनगर 16 अगस्त

कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केसः कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या का मामला और गंभीर हो गया है. इस घटना को लेकर देशभर के चिकित्सा समुदाय में आक्रोश है। फिर इस घटना का असर गुजरात पर भी पड़ा है. मृत डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है. जिसके चलते आज (16 अगस्त) ओपीडी और अन्य सेवाएं बंद रहेंगी. जबकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी.

कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में अहमदाबाद सिविल अस्पताल परिसर के बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है. घटना के विरोध में और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर आज काम से दूर रहेंगे. डॉक्टर आज ओपीडी सेवा बंद रखेंगे. साथ ही इमरजेंसी सेवा भी जारी रखने का फैसला लिया गया है.

वडोदरा के सयाजी अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आज ओपीडी और वार्डों सहित सभी गैर-आपातकालीन सेवाओं से दूर रहेंगे। इसके साथ ही 400 से ज्यादा डॉक्टरों ने विरोध करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है. इतना ही नहीं, जब तक वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स एसोसिएशन की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक डॉक्टरों का विरोध और हड़ताल जारी रहेगा.

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सूरत के सिविल अस्पताल में ओपीडी शुरू नहीं हुई है. कुछ ओपीडी खोल दी गई हैं. लेकिन, रेजिडेंट डॉक्टर नहीं आए। पता चला है कि डॉक्टरों के आने के बाद ओपीडी खोली जाएगी। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है. दूर-दराज से आने के कारण मरीज परेशान होते हैं। सिविल अस्पताल में कार्यरत इंटर्न और रेजिडेंट्स समेत करीब 700 से 800 डॉक्टर आपातकालीन सेवाओं से दूर रहे हैं। जब तक कड़ी कार्रवाई और न्याय नहीं मिलेगा, सुघी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.

सावरकर की टी शर्ट को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने कहा-गांधी का नाम मिटाने की कोशिश

सुरेन्द्रनगर (ईएमएस) जिले के चोटिला में तिरंगा यात्रा के दौरान वीर सावरकर की टी-शर्ट को लेकर राजनीति गरमा गई है तिरंगा यात्रा में शामिल स्कूली बच्चों ने सावरकर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी, जिसे कांग्रेस नेताओं ने उतरवा दिया था इस मामले में खिलाफ केस दर्ज कांग्रेस भड़क गई और आरोप लगाया कि भाजपा गांधीजी का नाम मिटाने का प्रयास कर रही है जानकारी के मुताबिक सुरेन्द्रनगर जिले की चोटीला से 7 किलोमीटर दूर सांगाणी प्राइमरी स्कूल से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी तिरंगा यात्रा में शामिल बच्चों ने सुभाषचंद्र बोस और वीर सावरकर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन रखी थी वैसे तो तिरंगे को देख हर गर्व से सलाम करता है, लेकिन यात्रा में शामिल बच्चों की टी शर्ट देख कांग्रेसी भड़क उठे कांग्रेसी नेताओं ने स्कूल के शिक्षकों को धक्का दिया और बच्चों की टी शर्ट उतरवा दी घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने पर सियासी पारा हाई हो गया कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋत्विक मकवाना ने भाजपा सरकार पर करते हुए कहा कि शिकायत पहले ही गृह मंत्री द्वारा पोस्ट की जा चुकी है। बच्चों के मन से गांधीजी का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा सांसद शक्तसिंह गोहिल की भी कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज कर पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि माफी मांगने वालों का इतिहास में जिक्र है उन्होंने कहा कि बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाने की वकालत करने वाले नेता पर मुकदमा दर्ज कियागया है सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है इसके अलावा हमारे नेता बच्चों को उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी थी,

देर रात बाहर न निकलें...गांधीनगर मेडिकल कॉलेज का अजीब सर्कुलर

अहमदाबादः पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेडी डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या से पूरे देश में जहां आक्रोश है। डॉक्टरों की तरफ से नो सिक्योरिटी, नो डयूटी के तहत प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी गुजरात के गांधीनगर मेडिकल कॉलेज की डीन ने सुरक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टरों के ऊपर ही डाल दी। डीन की तरफ से जारी किए सर्कुलर में मोटे तौर पर कहा गया है कि महिला डॉक्टर रात में बाहर न जाएं। वे रात में निकलने को टाल दें। अगर जरूरी हो तो वे किसी को साथ में लेकर ही जाएंगे। मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल में भी वे किसी महिला के साथ रहें या फिर परचित सहकर्मी को साथ रखें।

जीएमईआरएस द्वारा संचालित राज्य सरकार के गांधीनगर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. शोभना गुप्ता ने कहा है कि महिला डॉक्टर अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें। डीन शोभना गुप्ता ने यह आदेश भी डॉक्टरों और विद्यार्थियों के लिए जारी किया है। सर्कुलर में डीन की तरफ से महिला डॉक्टरों और स्टूडेंट्स से कहा गया है कि लेट नाइट बाहर न निकलें। कोई भी अप्रिय स्थिति में वे महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करें। सर्कुलर में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की घटना का जिक्र करते हुए डीन ने चेतावनी दी है कि अगर रात में बाहर निकलें तो किसी को साथ में लेकर जाएं।

डीन के सर्कुलर में महिला डॉक्टरों-नर्सो और छात्राओं के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इनका जिक्र नहीं किया गया है। सकुर्लर में गांधीनगर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कड़ी करने और आवांछित तत्वों के प्रवेश की मॉनीटरिंग किए जाने की भी जिक्र नहीं है। डीन ने पूरी तरह से अपनी सुरक्षा स्वयं करें के अंदाज में सर्कुलर जारी करके इतिश्री कर ली है। डीन के सर्कुलर को लेकर गांधीनगर मेडिकल कॉलेज के महिला स्टॉफ में नाराजगी है। उनका कहना है कि रात में बाहर निकलना और हर वक्त किसी को साथ में रखना कतई संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन को कम से कम हमें अलर्ट करने के साथ ही सीसीवीटी कैमरों की संख्या बढ़ाने और सुविधाएं देने के साथ गैरजरूरी लोगों की आवाजाही की मॉनीटरिंग पर फोकस करना चाहिए। गुजरात में कुल 40 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 23 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज पर जिस तरह से भीड़ ने हमला किया है। उसके बाद डॉक्टर और अधिक चिंतित हैं।

गुजरात सरकार का 'गरवी गुर्जरी' बना भारत सरकार का ट्रेडमार्क ब्रांड

गांधीनगर 16 अगस्त : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दे रही है। इन प्रयासों के चलते ही राज्य सरकार ने हथकरघा और हस्तकला क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार ने गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तकला विकास निगम लि. (जीएसएचएचडीसी) को उसके ब्रांड 'गरवी गुर्जरी' के लिए ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र दिया है। निगम ने अपने प्रसिद्ध ब्रांड 'गरवी गुर्जरी' के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।

उल्लेखनीय है कि निगम पिछले कई दशकों से हथकरघा और हस्तकलाकेउत्पादों के लिए एक एजेंसी केरूप में कार्य कर रहा है। भारत सरकारकी ओर से प्राप्त यह ट्रेडमार्कसर्टिफिकेट राज्य के हथकरघाऔरहस्तकलाक्षेत्र के विकासएवंसुरक्षा के नए आयाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री ललित नारायण सिंह सांदु ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से पिछले दो दशकों से लगातार राज्य की पारंपरिक कला-कारीगरी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इसके परिणामस्वरूप निगम के 'गरवी गुर्जरी 'ब्रांड कोभारत सरकार का ट्रेड मार्क सर्टिफिकेट हासिल हुआ है।

ट्रेडमार्क का पंजीकरण 'गरवी गुर्जरी' को हथकरघा एवं हस्तकला उत्पादों के विशाल बाजार में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस ट्रेडमार्क के कारण ग्राहक 'गरवी गुर्जरी' के उत्पादों को न केवल आसानी से पहचान पाएंगे, बल्कि उसे अन्य उत्पादों से अलग भी कर पाएंगे, जो बाजार में 'गरवी गुर्जरी' ब्रांड की मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए रक्षा कवच बनेगा ट्रेडमार्क :'गरवी गुर्जरी' ने ट्रेडमार्क के साथ अपने ब्रांड के उत्पादों को कानूनी तौर पर संरक्षित कर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल किया है। निगम ने इसके जरिए फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग के अवसरों के लिए अपने दरवाजे भी खोल दिए हैं और 'गरवी गुर्जरी' को अपना दायरा और राजस्व बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया है।

यह ट्रेडमार्क 'गरवी गुर्जरी' की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक रक्षा कवच के रूप में काम करेगा, साथ ही इससे अनधिकृत संस्थाओं द्वारा गुजरात की पारंपरिक कारीगरी के दुरुपयोग या गलत प्रस्तुतिकरण पर रोक लगेगी। निगम को इस ट्रेडमार्क के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी और वह ग्राहकों को 'गरवी गुर्जरी' उत्पादों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता का आश्वासन भी दे सकेगा। इसके साथ ही, हथकरघा एवं हस्तकला उत्पादों के निर्धारित मानकों को भी पूरा किया जा सकेगा, जो ग्राहक का विश्वास एवं संतोष को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने मनाया भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस

देश भर के 75 प्रमुख जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनियों का आयोजन

मुंबई, 17 अगस्त

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बैंक) ने कई नवोन्मेषी पहलों के साथ भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री देबदत्त चांद, कार्यपालक निदेशकों, सीवीओ और वरिष्ठ कार्यपालकों ने मुंबई स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में सहभागिता की।

बैंक और उसके कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा अभियान का भी बड़े उत्साह के साथ समर्थन किया। यह पहल देशभक्ति की भावना को प्रगाढ़ करने हेतु नागरिकों को अपने घरों और कार्यालयों में गर्व से तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा पोर्टल पर उसकी तस्वीरें पोस्ट करने के लिए आमंत्रित करती है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री देबदत्त चांद ने कहा, ठ भारत के 78 वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाते हुए आवश्यक है कि हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान भी करें जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया और एक ऐसे भविष्य के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें जहां हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए। चांद ने कहा, ठबैंक ऑफ़ बड़ौदा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास आकांक्षाओं को बल देने में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभाता रहा है और हम देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैंठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देश भर के बैंक कर्मचारियों ने ठविकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र ठ थीम के साथ जन जागरूकता अभियान ठनशा मुक्त भारत अभियान ठ के तहत नशीली दवाओं के विरोध की शपथ ली।

राजकोट रेल मंडल पर उत्साहपूर्वक मनाया गया 78वाँ स्वतंत्रता दिवस

राजकोट,16 अगस्त

पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल में 78 वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राजकोट स्थित डीआरएम ऑफिस प्रांगण में आयोजित समारोह में राजकोट मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री अश्वनी कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया, झण्डे को सलामी दी तथा सामारोहिक परेड का निरीक्षण किया।

श्री अश्वनी ने रेलकर्मियों को संबोधित कर उन्हें एवं उनके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी एवं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार मिश्र का सन्देश सुनाया। इसके बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में रेल कर्मचारियों द्वारा गाये गए गीतों एवं नृत्य प्रदर्शन ने पूरे माहौल को देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया।

स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री कौशल कुमार चौबे, पश्चिम रेलवे महिला समाज सेवा संगठन राजकोट की अध्यक्षा श्रीमती रंजना सिंह व उनकी टीम, मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री कमलेश्वर सिंह, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री मनीष मेहता, तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ रेल अधिकारी, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी व उनके परिजन उपस्थित थे।

इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर सोमवार, 19 अगस्त, 2024 को खुलेगा

अहमदाबाद, 14 अगस्त, 2024: इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भारत में लीडिंग टर्नकी प्री-इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है, जिसके पास डिजाइन और इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज है। कंपनी के पास प्री-इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स ("ईं") के इंस्टॉलेशन और इरेक्शन के लिए ऑन-साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी है। कंपनी ने अपनी पहले इनिशियल पब्लिक ऑफस के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर के लिए रु.850/- से रु.900/- का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी घ्ध्ध् सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार, 19 अगस्त, को खुलेगा और बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को बंद होगा। निवेशक न्यूनतम 16 इक्विटी

शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। उसके बाद 16 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है।

आईपीओ में 2,000 मिलियन रुपए तक का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स और इन्वेस्टर सेलिंग शेयरधारक द्वारा 44,47,630 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल (ध्इए) शामिल है। ऑफर में पात्र कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रुपए का रिजर्वेशन और प्रति शेयर 85 रुपए का एम्प्लॉई डिस्काउंट शामिल है।

फ्रेश इश्यू से जुटाए पैसों में से, 585.26 मिलियन रुपए तक का इस्तेमाल प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024 के दौरान ऑपरेशन से इंटरार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का रेवेन्यू पिछले वर्ष के 11,239.26 मिलियन रुपए से बढ़कर 12,933.02 मिलियन रुपए हो गया।

एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड, और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर का रजिस्ट्रार है। इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है।

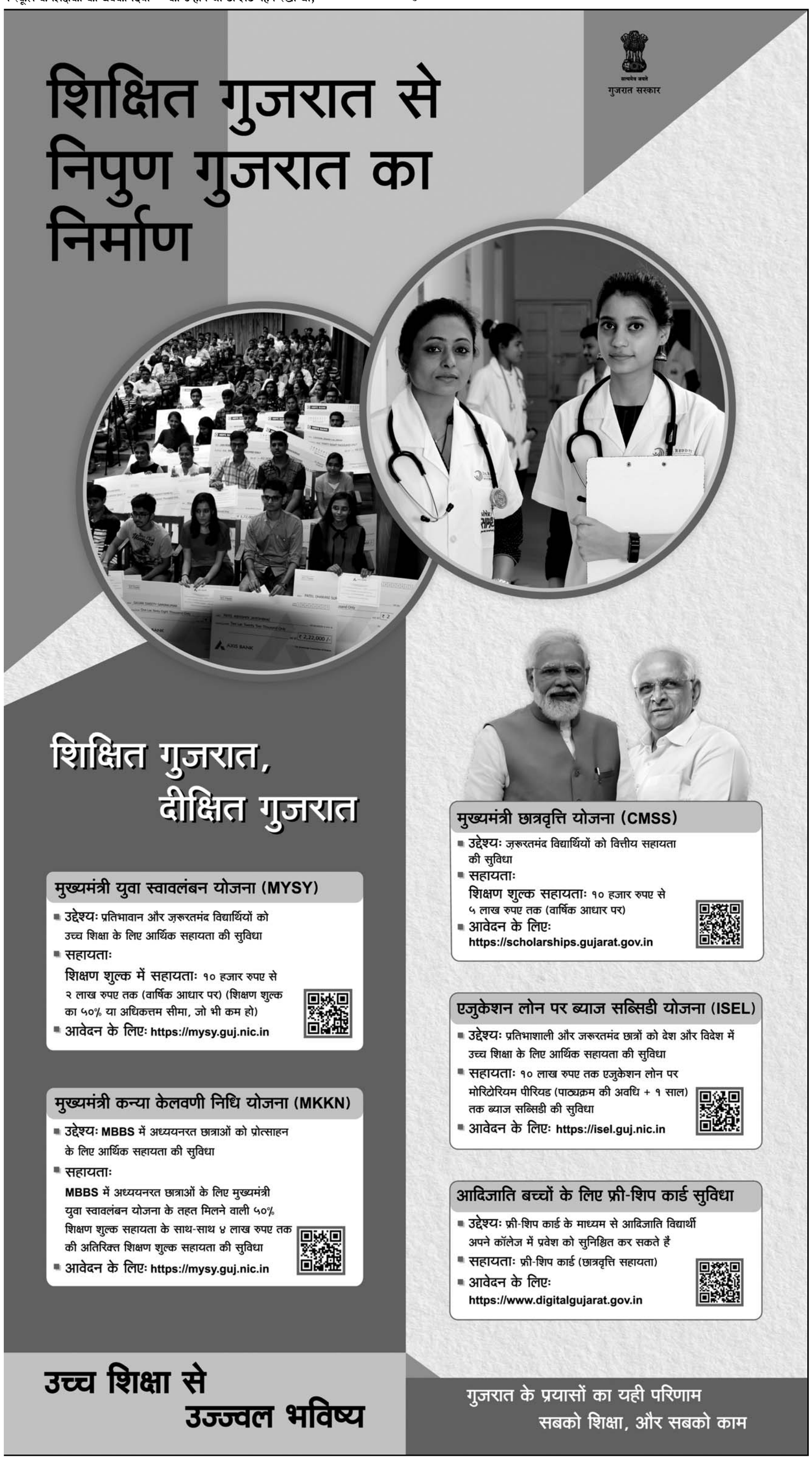

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95